**Fourteenth Loksabha**

**Session : 4**
**Date : 23-03-2005**

**Participants : Acharia Shri Basudeb**

Title: Need for according clearance to the 111 pending irrigation projects proposed to be set up in various parts of the country.

**श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद)** : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में सबसे अधिक आय का स्रोत कृषि है। हमारे देश में जो 411 सिंचाई की योजनाएं थीं, उनमें मुश्किल से 28 योजनाओं का निपादन हो सका है, जबकि योजना आयोग ने इस पर भरपूर ज़ोर दिया है। इन योजनाओं में कुल 77 हजार करोड़ रुपये का खर्च था। समय से पूरा न होने के कारण आज इस पर 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च बढ़ गया है। पूरे देश में कृषि क्षेत्र में 14 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और उसकी सिंचाई के साधन मात्र एक तिहाई हैं। इसमें सिर्फ 6000 करोड़ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो पाती है, बाकी क्षेत्र असिंचित पड़ा हुआ है। राज्यों को जो पैसा दिया जाता है, या योजना आयोग जो मांग करता है, वह पैसा राज्यों को पर्याप्त न मिलने के कारण सिंचाई की सुविधाएं बाधित हो रही हैं और कृषि क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र न बढ़ पाने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए लाजमी है कि हमारी केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के मुताबिक, उसकी संस्तुतियों के मुताबिक, देश में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए पैसा उपलब्ध कराए जिससे कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ सके और हमारा देश सम्पन्न हो सके।